



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2013
(BIIADRA 19, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 10th September, 2013

No. 30—HLA of 2013/77.—The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 30—HLA of 2013

**THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SALARY,
ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)
AMENDMENT BILL, 2013**

A

BILL

further to amend the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Salary, Short title,

Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2013.

Amendment of section 2A of Haryana Act 2 of 1975.

2. In section 2A of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), for the words "twenty thousand rupees", words "thirty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 3A of Haryana Act 2 of 1975.

3. In section 3A of the principal Act, for the words "twenty thousand rupees", words "thirty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 3C of Haryana Act 2 of 1975.

4. In section 3C of the principal Act, for the words "five thousand rupees", words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 4 of Haryana Act 2 of 1975.

5. In sub-section (1) of section 4 of the principal Act, for the words "forty thousand rupees", words "fifty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 6 of Haryana Act 2 of 1975.

6. In sub-section (3) of section 6 of the principal Act, for the words "rupees ten thousand", words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present MLAs are being paid Salary @Rs. 20,000/- per month, Constituency Allowance @Rs. 20,000/- per month, Office Allowance @Rs. 5,000/- per month and Telephone Allowance @Rs. 10,000/- per month and Salary of Leader of Opposition @Rs. 40,000/- per month under the provisions of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

Keeping in view the rise in the cost of living, the Government has decided to increase the Salary of Members of Legislative Members from Rs. 20,000/- per month to Rs. 30,000/- per month, Constituency Allowance from Rs. 20,000/- per month to Rs. 30,000/- per month, Office Allowance from Rs. 5,000/- per month to Rs. 10,000/- per month and telephone allowance from Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/- per month and salary of the Leader of Opposition from Rs. 40,000/- per month to Rs. 50,000/- per month.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 10th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed increase in Salary, Constituency Allowance, Office Allowance and Telephone Allowance of Members of Legislative Assembly and Salary of the Leader of Opposition will entail an extra expenditure of approximately Rs. 2,80,20,000/- (Rs. two crore eighty lacs twenty thousand only) per year from the State Exchequer.

प्राधिकृत अनुवाद

2013 का विधेयक संख्या 30—एच०एल०ए०

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2013
हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन)
अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। -

1 यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

2 हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2क में, "बीस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "तीस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 2क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3क में, "बीस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "तीस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3ग में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ग का संशोधन।

5 मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, "चालीस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 4 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) में, "दस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 6 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन भत्ता तथा पेशन) अधिनियम, 1975 के प्रावधान अनुसार विधान सभा सदस्यों को वेतन 20,000/- रुपए प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 20,000/- रुपए प्रतिमाह, कार्यालय भत्ता 5,000/- रुपए प्रतिमाह तथा दूरभाष भत्ता 10,000/- रुपए प्रतिमाह एवं नेता प्रतिपक्ष को वेतन 40,000/- रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है।

जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के दृष्टिकोण, सरकार ने निर्णय लिया है कि विधान सभा सदस्यों का वेतन 20,000/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ा कर 30,000/- रुपए प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 20,000/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ा कर 30,000/- रुपए प्रतिमाह, कार्यालय भत्ता 5,000/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ा कर 10,000/- रुपए प्रतिमाह तथा दूरभाष भत्ता 10,000/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ा कर 15,000/- रुपए प्रतिमाह एवं नेता प्रतिपक्ष का वेतन 40,000/- रुपए से बढ़ा कर 50,000/- रुपए प्रतिमाह कर दिया जाए।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,

संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 10 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,

सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

विधान सभा के सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता तथा दूरभाष भत्ता एवं नेता प्रतिपक्ष के वेतन में प्रस्तावित बढ़ोतरी करने पर राजकोष पर रुपए 280,20,000/- (दो करोड़, अस्सी लाख, बीस हजार रुपए) प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्चा आएगा।